भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *17

(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़,1947 (शक) को दिया जाना है)

बढ़ती महंगाई का प्रभाव

*17. श्री जिया उर रहमान:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेषकर गरीबों और युवाओं के रोजगार के स्तरों और घरेलू आय पर बढ़ती महंगाई के प्रभाव का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा महंगाई को नियंत्रित करने और सभी क्षेत्रों में सतत् रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्री

(श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्री जिया उर रहमान द्वारा "बढ़ती महंगाई का प्रभाव" के संबंध में पूछे गए दिनांक 21 जुलाई, 2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): सरकार ने विशेष रूप से गरीबों और युवाओं के लिए सतत रोजगार और घरेलू आय में सुधार करते हुए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, आवश्यक खाद्य वस्तुओं के लिए सुरक्षित भंडार में वृद्धि, खरीदे गए अनाज की खुले बाजार में युक्तिपूर्ण बिक्री, कम आपूर्ति के दौरान आयात और निर्यात नियंत्रण की सुगमता, बाजार में चुनिंदा वस्तुओं की अधिक आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए स्टॉक सीमा को लागू करना, चुनिंदा खाद्य पदार्थों की भारत ब्रांड के तहत रियायती दरों पर खुदरा बिक्री, और खास कर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 81 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण तथा ₹12 लाख (और मानक कटौती के साथ वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए ₹12.75 लाख) तक की वार्षिक आय को आयकर से छूट देकर व्यक्तियों की प्रयोज्य आय में वृद्धि करना शामिल है। विभिन्न उपायों के फलस्वरूप, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा परिमित औसत खुदरा मुद्रास्फीति दर (वर्ष दर वर्ष) 2023-24 में 5.4 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 4.6 प्रतिशत हो गई, जो पिछले 6 वर्षों में सबसे कम है। इसके अलावा, 2025-26 की पहली तिमाही में सीपीआई घटकर 2.7 प्रतिशत के औसत तक रह गई, जो जून 2025 की तिमाही के अंत में 2.1 प्रतिशत थी। खाद्य मुद्रास्फीति में कमी 2025-26 की पहली तिमाही तक जारी रही और जून 2025 में (-) 1.06 प्रतिशत के साथ नकारात्मक हो गई, जो जनवरी 2019 के बाद सबसे कम है।

मुद्रास्फीति नियंत्रण उपायों के अलावा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, उद्योगों को रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन, राष्ट्रीय शहरी/ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, कौशल विकास योजना आदि जैसे विभिन्न रोजगार सृजन और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा, महिलाओं, युवाओं और छोटे किसानों आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौशल, निवेश और प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में अल्प-रोजगार का समाधान करने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में 'ग्रामीण समृद्धि और समुत्थानशीलता' कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अखिल भारतीय वार्षिक बेरोजगारी दर (सामान्य स्थिति के अनुसार) 2017-18 में 6 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 3.2 प्रतिशत हो गई।

*****